CEDSI TIMES

Your Skilling Partner...

कृषि मंत्री ने बैंकों से डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा देने का आग्रह किया

कृषि मंत्री एस. निरंजन रेड्डी ने बैंकों से तेलंगाना में डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा देने का आग्रह किया है।

मंत्री ने दिसंबर 2022 को समाप्त तिमाही के लिए बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए तेलंगाना राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में बढ़ती मांग के बीच अन्य राज्यों से दूध कैसे खरीदा जा सकता है।

श्री रेड्डी ने कहा कि डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा देकर बैंक डेयरी और डेयरी उत्पादों में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देंगे।

इस वित्तीय वर्ष दिसंबर तक बैंकों के प्रदर्शन पर एक प्रस्तुति में, एसएलबीसी अध्यक्ष और भारतीय स्टेट बैंक के सीजीएम अमित झिंगरान ने कहा कि बैंकों की कुल जमा राशि 15,105 करोड़ रुपये बढ़कर 6,47,630 करोड़ रुपये हो गई। कुल अग्रिम ₹37,380 करोड़ बढ़कर ₹769,713 करोड़ हो गया। सीडी अनुपात 118.85% रहा।

जम्मू और कश्मीर: 18 महीनों में 1500 से अधिक सहकारी समितियों का गठन किया गया

सहकारिता विभाग द्वारा की गई विभिन्न पहलों को गिनाते हुए, आयुक्त सचिव, यशा मुद्गल ने कहा कि पूरे जम्मू और कश्मीर में 18 महीनों में 1500 से अधिक सहकारी समितियों का गठन किया गया।

सहकार भारती और जेएंडके डेयरी कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के सहयोग से लीड एलजेके इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डायलॉग (एलईएडी) द्वारा आयोजित सहकारी विकास पर एक संगोष्ठी के दौरान बोलते हुए, यहां कारगिल भवन में जम्मू-कश्मीर में सहकारी आंदोलन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया। सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए सरकार का जनादेश और सहकारी बैंकों और सहकारी प्रशिक्षण संस्थानों सहित सहकारी विकास के लिए आवश्यक संस्थानों के पुनरुद्धार के लिए विभाग द्वारा की गई विभिन्न पहल।

सरकार ने विभिन्न पशुधन और कुक्कुट प्रजातियों की 38 देशी नस्लों को 'खतरे में' बताया

सरकार ने जानकारी दी है कि देश में विभिन्न पशुधन और कुक्कुट प्रजातियों की 38 देशी नस्लें 'खतरे में' हैं। आज संसद में एक प्रश्न के उत्तर में, मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि 14 देशी नस्लें असुरक्षित हैं, 19 नस्लें संकटग्रस्त हैं और 5 नस्लें संकटग्रस्त श्रेणी में हैं।

उन्होंने आगे कहा कि करनाल (हरियाणा) में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)-राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (एनबीएजीआर) देश में पशुधन के पंजीकरण का ख्याल रखता है। उन्होंने कहा कि अब तक कुल 212 स्वदेशी पशु नस्लों को पंजीकृत किया गया है, जिसमें पशुधन की 187 नस्लें, पोल्ट्री की 22 नस्लें और कुत्तों की तीन नस्लें शामिल हैं।

तमिलनाडु सरकार ने 14,000 करोड़ रुपये के फसल ऋण, पशुपालन के लिए 1500 करोड़ रुपये आवंटित किए

कृषि मंत्री एमआरके पन्नीरसेल्वम ने घोषणा की कि तमिलनाडु सरकार 2023-2024 के दौरान राज्य में किसानों को कुल 14,000 करोड़ रुपये के सहकारी फसल ऋण और बकरी पालन, डेयरी, मुर्गी पालन और मछली पालन के लिए कुल 1,500 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त सहकारी ऋण देगी।

मंत्री के अनुसार, सहकारी एजेंसी ने 2022-2023 में 1.643 मिलियन किसानों को 12,648 करोड़ रुपये का फसली ऋण दिया। पिछले दस वर्षों के औसत के अनुसार, "यह 89% की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है," उन्होंने कहा।

उन्होंने कहा कि छह साल बाद 11.19 मिलियन मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है, जो 2020-21 की तुलना में 1.17 मिलियन मीट्रिक टन अधिक है।

सरकार इजरायल, नीदरलैंड, थाईलैंड, मिस्र, मलेशिया और फिलीपींस जैसे देशों में अपनी प्रथाओं को सीखने के लिए 150 किसानों के विदेशी प्रशिक्षण को शामिल करते हुए 3 करोड़ रुपये की परियोजना शुरू कर रही है।

"बाजरा के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष" के अनुरूप, मंत्री ने तमिलनाडु मिलेट मिशन का भी प्रस्ताव दिया है। मंत्री ने कहा, "50,000 एकड़ में बाजरा के माध्यम से फसल विविधीकरण लाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी।"

सरकार 32 जिलों में 14,500 हेक्टेयर में 725 क्लस्टर भी स्थापित करेगी और जैविक खेती के मूल्य पर किसानों, ग्रामीण युवाओं, कृषि महिलाओं और छात्रों को शिक्षित करेगी।

वॉलमार्ट फाउंडेशन का लक्ष्य आजीविका में सुधार के लिए 1 मिलियन किसानों तक पहुंचना है

भारत में किसानों की आजीविका में सुधार के लिए अपनी प्रतिबद्धता का विस्तार करते हुए, वॉलमार्ट फाउंडेशन ने घोषणा की कि इसका लक्ष्य 2028 तक 50% महिलाओं सहित अतिरिक्त 10 लाख किसानों तक पहुंचना है।

अपनी 5 साल की रणनीति के हिस्से के रूप में, संगठन महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में 24 एफपीओ और 30,000 छोटे किसानों तक पहुंचने के लिए $3 मिलियन का निवेश करेगा, जबकि ओडिशा में 1,000 महिला छोटे किसानों तक पहुंचने के लिए $533,876 अनुदान का उपयोग किया जाएगा, उन्हें दो एफपीओ से जोड़ा जाएगा।

"वॉलमार्ट फाउंडेशन की नवीनतम प्रतिबद्धता 800,000 से अधिक छोटे किसानों का समर्थन करेगी और उन्हें बाजार तक पहुंच प्रदान करेगी, जो सभी हितधारकों के लिए साझा मूल्य बनाने में मदद करेगी," परोपकारी संगठन के कार्यकारी उपाध्यक्ष और मुख्य स्थिरता अधिकारी कैथलीन मैकलॉघलिन ने एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा। नयी दिल्ली।

महिला किसानों के लाभ पर विशेष ध्यान देने के साथ, वॉलमार्ट फाउंडेशन का लक्ष्य कई राज्यों में छोटे किसानों को स्थायी कृषि विधियों और प्रौद्योगिकी पर प्रशिक्षित करना है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और ओडिशा सहित, और अनुदान के नए सेट के माध्यम से अपनी आय बढ़ाने के लिए।

यह पांच साल की रणनीति 2018 से भारत में किसानों की आजीविका में सुधार करने और वाणिज्यिक सामान बाजारों तक उनकी पहुंच बढ़ाने के लिए वॉलमार्ट फाउंडेशन के निवेश का विस्तार है। वॉलमार्ट फाउंडेशन ने कई राज्यों में 16 अनुदानकर्ताओं के साथ 24 अनुदान कार्यक्रमों के माध्यम से भारत में छोटे किसानों का समर्थन करने के लिए $39 मिलियन से अधिक के परोपकारी अनुदानों का वित्त पोषण किया है।

सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए सरकार की PMFME योजना 25,000 से अधिक ऋण स्वीकृत करती है

सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना (पीएमएफएमई) का औपचारिककरण, जो सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना या उन्नयन के लिए क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी प्रदान करता है, को अब तक 1,02,515 से अधिक ऋण आवेदन प्राप्त हुए हैं। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, प्राप्त आवेदनों में से 25,774 ऋण आवेदन स्वीकृत किए गए हैं।

यह योजना 2020-21 से 2024-25 की पांच साल की अवधि के दौरान 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी के माध्यम से 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना का समर्थन करती है।

ऋण सहायता के अलावा, इस योजना में व्यक्तिगत सूक्ष्म-खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को योजना के तहत ऋण से जुड़े अनुदान के साथ या बिना, सूक्ष्म-खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के श्रमिकों और स्वयं सहायता समूहों, किसान उत्पादक जैसे समूहों को प्रशिक्षित करने के लिए एक क्षमता-निर्माण घटक भी है। योजना के कार्यान्वयन में लगे सरकारी अधिकारियों और अन्य लोगों के अलावा संगठन और सहकारी समितियाँ।

महत्वपूर्ण रूप से, मंत्रालय ने कई सरकारी उद्यमों और विभागों के साथ समझौता ज्ञापन या संयुक्त पत्रों पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR), पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD), भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI), ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD), आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA), और पीएमएफएमई योजना को अन्य सरकारी योजनाओं के साथ अभिसरण करने, क्षमता निर्माण, विपणन और योजना की बढ़ती पहुंच में लाभार्थियों की पहचान करने और सहायता करने के लिए।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने कहा कि इस क्षेत्र को आसान और किफायती ऋण के लिए सभी खाद्य और कृषि प्रसंस्करण गतिविधियों को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के तहत पात्र बनाया गया है, जबकि 2,000 करोड़ रुपये का विशेष कोष निर्धारित किया गया है। इन उद्यमों का समर्थन करने के लिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD) में।

मध्य प्रदेश में अगले महीने शुरू होगी पशु एंबुलेंस

अगले महीने से राज्य में 400 से अधिक पशु एंबुलेंस चलने लगेंगी और इसके लिए एक कॉल सेंटर स्थापित किया जा रहा है।

बीमार पशुओं को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 406 पशु चिकित्सा इकाई (पशु एंबुलेंस) तैयार करने की प्रक्रिया भोपाल में चल रही है। पशुपालन मंत्री प्रेमसिंह पटेल ने कहा कि इस व्यवस्था को अप्रैल से शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंसान बीमार पड़ने पर अस्पताल पहुंच सकता है, लेकिन जानवर नहीं पहुंच सकता। ऐसे जानवरों के लिए प्रदेश में यह व्यवस्था शुरू की जा रही है। प्रदेश के लिए स्वीकृत 406 पशु एंबुलेंस केन्द्र सरकार से प्राप्त हो चुकी है।

जिला पशु कल्याण समिति को पूरी तरह से निर्मित वाहन उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। पशु चिकित्सा, ईंधन और रखरखाव के लिए प्रति वाहन 68 हजार रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। पशुपालन एवं डेयरी निदेशालय राज्य स्तर पर कॉल सेंटर का संचालन, नियंत्रण और निगरानी करेगा। पशु एम्बुलेंस केंद्र सरकार की एक पहल है और इसे मप्र में लागू किया जाएगा। मार्च 2022 में पेश किए गए राज्य के बजट में इसकी घोषणा की गई थी।

हम कौन हैं?

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत भारतीय कृषि कौशल परिषद (ASCI) के तत्वावधान में काम करने वाली एक स्वायत्त संस्था "भारत में डेयरी कौशल के लिए उत्कृष्टता केंद्र (CEDSI)", किसानों की आजीविका के सशक्तिकरण और बेहतरी में मदद करने के लिए, वेतनभोगी कर्मचारी, और डेयरी मूल्य श्रृंखला में अन्य हितधारक।

सीईडीएसआई सदस्यता उद्योग के नेताओं, नीति निर्माताओं, विकास चिकित्सकों, डेयरी वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, छात्रों और किसानों को डेयरी उद्योग के लिए आसन्न महत्व के मुद्दों पर बहस और चर्चा करने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करेगी।